vkckek! oki l tkvk   25&26 tuojh   vkckek! oki l tkvk

दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी
अमेरिकी साम्राज्यवाद का सरगना
ओबामा के भारत दौरे का पुरजोर विरोध करो!
26 जनवरी,2015 को विरोध दिवस मनाओ!

l;kj ykxk!

फिर एक बार अमेरिकी साम्राज्यवाद का सरगना ओबामा भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार वो देश के 65 वें गणतंत्र दिवस के आयोजन का मुख्य अतिथि बनकर दिल्ली में सलामी लेने पहुंच रहे हैं। देश के शासक वर्गों एवं विदेशी कारपोरेट घरानों का दलाल, प्रधान सेवक व गुलाम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत यात्रा पर आने वाले ओबामा चूंकि दुनिया के उत्पीड़ित देशों व जनता का अव्वल नंबर का दुश्मन व सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका साम्राज्यवाद का सरगना है, इसलिए उन्हें भारत की धरती पर कदम रखने का नैतिक अधिकार नहीं है। 65 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ओबामा को सलामी देने का मतलब है, साम्राज्यवाद की गुलामी। दबाव, धौंस, हमलों व कब्जे के जरिए दुनिया की उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का बेरहमी से शोषण व दमन करने वाला, बदनाम तानाशाहों को सत्ता पर बिठाने वाला, सहयोग नहीं देने वालों का सफाया या सत्ता पलट करवाने वाला, विश्व के तेल, खनिज व अन्य तमाम सम्पदाओं और संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने वाला, अपने आर्थिक व वित्तीय संकट के बोझ को पिछड़े देशों के कंधों पर लादने वाला, अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए कत्लेआम करने वाला हत्यारा, युद्धोन्मादी, रंगभेदी साम्राज्यवादी अमेरिका विश्व जनता का नम्बर एक दुश्मन है। ऐसे देश के अध्यक्ष को सलामी देने का निर्णय जनविरोधी, देशद्रोही कदम है, देश की संप्रभुता के साथ भद्दा मजाक है और प्रगतिशील, जनवादी, देशभक्त एवं आजाद व अमन पसंद जनता का अपमान है। अन्य दलाल संसदीय पार्टियां एनडीए सरकार की अमेरिकी परस्त नीतियों के सुर में सुर मिला रही हैं।

vkckek dk nkjk & dkjikjV yV o Qklhoknh neu e Hkkjh c<kRrjh dk ldr!

अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकों की कारपोरेट परस्त व जन विरोधी नीतियों के चलते 2008 में उत्पन्न सब प्राइम संकट ने अमेरिकी अर्थ व्यवस्था को खोखला बनाते हुए देशव्यापी एवं विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया है। अमेरिका में अभूतपूर्व ढ़ंग से बेरोजगारी बढ़ रही है। ओबामा तो सैकडों अरब डॉलरों का जन–धन एकाधिकारी कार्पोरेट संस्थाओं की जेबों में पहुंचाकर अमेरिकी जनता को, खासकर श्रमिकों व मध्यम वर्ग को बेहिसाब तकलीफें पहुंचा रहे हैं। उसने जन कल्याणकारी योजनाओं में कई कटौतियां की। इसके बावजूद संकट के भंवर से बाहर आने में नाकाम ओबामा पिछड़े व गरीब देशों के संसाधनों की लूट–खसोट में और ज्यादा तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। ओबामा अब इसलिए आ रहे हैं कि कई और समझौते करके अपने संकट का बोझ भारत पर और ज्यादा लादा जा सके। हमारे देश के संसाधनों को मनमाने लूटने में बहुत बड़ी रुकावट बने माओवादी आंदोलन समेत सभी जन आंदोलनों का और ज्यादा क्रूरतापूर्वक दमन करने में सलाह–सुझाव देने के लिए वो यहां आ रहे हैं।

i/kku e=h ugh & dkjikjV ?kjkuk dk nyky o i/kku lod g] ujn eknh

प्रधान मंत्री बनते ही मोदी ने अपनी कारपोरेट सेवा के तहत प्रतिरक्षा, बीमा, रेल्वे व खुदरा व्यापार में 49.6 प्रतिशत एफडीआई, सरकारी, निजी क्षेत्रों की भागीदारी व पहलकदमी के साथ परियोजनाओं का निर्माण, महत्वपूर्ण पीएसयु का विनिवेशीकरण, सब्सिडियों में कटौती, 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण, सेज का निर्माण, विदेशी निजी पूंजीनिवेश के साथ बुलेट ट्रेन प्राजेक्ट, टेक्सटाइल, टेलिकाम क्षेत्रों में एफडीआई का प्रवेश आदि तमाम योजनाएं कारपोरेट वर्गों के ही हित में अपनायी। श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी सुधार लाये जा रहे हैं। आदिवासियों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन करके जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है।

राष्ट्रीयता, देशभक्ति, स्वदेशी आदि नारे दरअसल स्वदेशी, विदेशी कारपोरेट शक्तियों की सेवा के ही लिए हैं। मोदी का 'मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया' वास्तव में विदेशी निवेशकों के लिए 'लूट इंडिया' आह्वान है। गरीब जनता खाना, कपड़ा, मकान, इलाज,शिक्षा, रोजगार, पेयजल, सिंचाई आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बीमारी, आवासहीनता आदि समस्याओं से जूझ रही है। लेकिन मोदी के एजेण्डे में आम जनता नहीं है।

nfu;k dh turk dk v0oy ucj dk n'eu & vefjdh lkezkT;okn

साम्राज्यवाद क्रूरतापूर्वक एवं आमानवीय, बर्बर तरीके से शासन व शोषण करता है। अमेरिकी शासक वर्गों के 500 सालों के इतिहास का आधा भाग स्थानीय जनजातियों के कत्लेआम, आदिवासी हनन एवं अपनी सत्ता को कायम करने में ही बीता। बाकी आधा भाग आफ्रिका से बंदी बनाकर लाये गये गुलामों की संतानों को उत्पीड़ित करने, उनके जान–माल के साथ खिलवाड़ करने एवं उत्पीड़ित देशों व जनता का शोषण–दमन करने का इतिहास है। अमेरिका में कालों के प्रति हीन भावना, दमन, रंगभेद नीति आज भी जारी है।

9/11 के हमलों के बाद 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' के नाम से जार्ज बुश द्वारा शुरू किए गए फासीवादी हत्याकाण्ड को ओबामा जारी रखते हुए अल क़ायदा, तालिबान और इस्लामिक आतंकवादियों के दमन के नाम पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। अमेरिका यह कहते हुए कि इस्लामिक आईएसआईएल या आईएसआईएस, इराक एवं सिरिया में हिंसा कर रहा है, इन पर हवाई हमले कर रहा है। अपने अदम्य साहस व प्रतिराध के साथ अमेरिका को कागजी शेर के रूप में दुनिया के सामने नंगा कर रही है, इराकी जनता। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' के नाम पर देशों पर हमलें, कब्जा, आर्थिक शोषण, सैनिक तख्ता पलट की कार्रवाइयां, जबरिया सत्ता परविर्तन, जनविरोधी तानाशाही शासकों का समर्थन, आम जनता का कत्लेआम, पूर्व नियोजित निहित स्वार्थपूर्ण युद्धतंत्र आदि ने अमेरिका को दुनिया के उत्पीड़ित देशों व जनता का अव्वल नंबर का दुश्मन बना दिया है।

अमेरिका दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा लागू दखलंदाजी और लूट–खसोट की नीतियों का समर्थन कर रहा है। चीन को घेरने वाली अमेरिकी भू–राजनैतिक रणनीति में भारत सरकार अमेरिका के मोहरे की तरह काम कर रही है। अमेरिका इस क्षेत्रा में भारत और पाकिस्तान दोनों को अपने इशारों पर नचवाते हुए दूसरी तरफ यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन दोनों के बीच दुश्मनी बरकरार रहे।

जब तक साम्राज्यवाद रहेगा, पर्यावरण की सुरक्षा असंभव है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना ही कारपोरेट घरानों का लक्ष्य होता है। साम्राज्यवाद का मतलब ही युद्ध है। उसने दुनिया की जनता को भूख और मौत के सिवाय कुछ नहीं दिया है। साम्राज्यवादी विरोधी राजनीतिक, आर्थिक प्रचार, जन गोलबंदी, जन प्रतिरोध एवं जनयुद्ध आज की एतिहासिक जरूरत है।

>Bs x.kra= fnol dk fojks/k djks!

भारत के संविधान जिसके लागू होने के उपलक्ष्य में हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, की पीठिका में भारत को संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है जो कि बहुत बड़ा ढ़कोसला है। देश के तमाम मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप बेरोकटोक जारी है। यहां यह उल्लेख करना लाजिमी होगा कि 27 अप्रैल, 2005 को भाकपा (माओवादी) पर पाबंदी लगायी। अमेरिकी साम्राज्यवादियों की आर्थिक व विदेशी लुटेरी नीतियों का भारत बेशर्मी से समर्थन करता आ रहा है। संविधान की पीठिका में समाजवादी शब्द को तो जनता को भरमाने के लिए ही रखा गया है। धर्मनिपेक्षता संविधान के कागजों तक ही सीमित है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद सरकारी संरक्षण में संघ परविार हिंदुत्व के एजेण्डे पर आगे बढ़ रहा है। कामन सिविल कोड़, धारा 370, राममंदिर, गीता को राष्ट्रीय किताब का दर्जा देने, शाला – महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाने आदि मुद्दें योजनाबद्ध तरीके से उछाले जा रहे हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमान व ईसाइयों पर हमलें लगातार बढ़ रहे हैं। घर वापसी के नाम पर मुसलमानों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम पर होने वाले आम चुनाव एक प्रहसन बनकर रह गये हैं। देशी–विदेशी पूंजीपतियों की पंसदीदा पार्टी व व्यक्ति को ही सत्ता में बैठाया जाता है।

ns'k ds etnj&fdlkuksa] Nk=&;qokvksa] f'k{kd&deZpkfj;ksa] i\xfr'khy&ns'kHkDr&tuoknh rkdrks!

झूठे गणतंत्र दिवस के आयोजनों का बहिष्कार करते हुए आगामी 26 जनवरी, 2015 को विरोध दिवस मनाओ। गांव, कस्बों व शहरों में 25–26 जनवरी, 2015 को मोदी–ओबामा विरोधी प्रदर्शनों, रैलियों का आयोजन करो। हर संभव तरीके में विरोध दर्ज करो। इस शोषणमूलक सत्ता को उखाड़ फेंककर नवजनवादी गणराज्यों के भारतीय फेडरेशन की स्थापना के लिए जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध के समर्थन में आगे आओं। इस जनयुद्ध को खत्म करने के लिए भारत की उत्पीड़ित जनता पर अमेरिकी साम्राज्यवाद की मदद् से केंद्र–राज्य सरकारों के द्वारा जारी नाजायज युद्ध – ऑपरेशन ग्रीनहंट का विरोध करो। मोदी की हिन्दुत्व फासीवादी सरकार के खिलाफ संगठित, मजबूत व जुझारू जन आंदोलन का निर्माण करने आगे आओ। दुनिया के उत्पीड़ित राष्ट्रों व जनता के अव्वल नंबर का दुश्मन व आतंकी साम्राज्यवादी अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद करो।

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)